उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल।

अध्याय VII, नियम 32(2)(ख)

मामले का विवरण

निर्णय की तिथिः 23 फरवरी, 2006

द्वितीय अपील संख्या 1506/2001

(पुराना नंबर 2701/1997)

1. उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा
कनखल, हरिद्वार

माध्यम सेः
महंत गोपाल दास (मृतक)
चेला महंत सोहन दास
(अब महंत राजेंद्र दास के माध्यम से)
निवासी–उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा।

2. महंत गोपाल दास (दिवंगत)
चेला महंत सोहन दास
निवासी–उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा,
कनखल, हरिद्वार।

2/1 महंत राजेंद्र दास
उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा
कनखल, हरिद्वार

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता।

बनाम

1. महंत दूज दास (मृतक)
चेला महंत टहल दास
निवासी–भीटीवाला, तहसील मुक्तसर,
जिला–फिरोजपुर, पंजाब.....

1/1 संत दयाल दास
चेला महंत दूज दास
निवासी–भीटीवाला, मुक्तासर, जिला फिरोजपुर, पंजाब।

.....वादी/प्रतिवादी।

2. श्री पराग दास
चेला महंत टहल दास,
निवासी–बधी पंच भादसन

जिला–पटियाला, पंजाब।

3. श्री ईश्वर दास
चेला महंत टहल दास
निवासी–गांव करारवाला
तहसील–फूल, जिला–भटिंडा, पंजाब।

4. महंत हरि दास
चेला महंत टहल दास
निवासी–शेखा, तहसील बरनाला,
जिला–संगरूर, पंजाब।

.....प्रतिवादी / प्रतिवादी।

श्री अजीत कुमार, अधिवक्ता की सहायता से श्री राजेंद्र डोभाल, विद्वान वकील अपीलकर्ताओं।
श्री एस.पी. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एल.एस. सामंत और श्री शरद द्वारा सहायता प्रदान की गई प्रतिवादियों के वकील हैं।

एएफआर (रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित)

रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित नहीं।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत)

दिनांकः 23.02.2006

फैसला सुरक्षित

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल।

द्वितीय अपील संख्या 1506 / 2001

(पुराना नंबर 2701 / 1997)

1. उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा
कनखल, हरिद्वार
माध्यम सेः
महंत गोपाल दास (मृतक)
चेला महंत सोहन दास
(अब महंत राजेंद्र दास के माध्यम से)
निवासी–उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा,
कनखल, हरिद्वार।

2. महंत गोपाल दास (दिवंगत)
चेला महंत सोहन दास
निवासी–उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा,
कनखल, हरिद्वार।

2 / 1 महंत राजेंद्र दास
उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा
कनखल, हरिद्वार

.....प्रतिवादी / अपीलकर्ता।

बनाम

1. महंत दूज दास (मृतक)
चेला महंत टहल दास
निवासी–भीटीवाला, तहसील मुक्तसर,
जिला–फिरोजपुर, पंजाब.....

1 / 1 संत दयाल दास
चेला महंत दूज दास
निवासी–भीटीवाला, मुक्तासर, जिला फिरोजपुर, पंजाब।

.....वादी / प्रतिवादी।

2. श्री पराग दास
चेला महंत टहल दास,
निवासी–बधी पंच भादसन
जिला–पटियाला, पंजाब।

3. श्री ईश्वर दास
चेला महंत टहल दास
निवासी–गांव करारवाला
तहसील–फूल, जिला–भटिंडा, पंजाब।

4. महंत हरि दास
चेला महंत टहल दास
निवासी–शेखा, तहसील बरनाला,
जिला–संगरूर, पंजाब।

.....प्रतिवादी / प्रतिवादी।

श्री राजेंद्र डोभाल की सहायता से एडवोकेट श्री अजीत कुमार ने यह जानकारी प्राप्त की। अपीलकर्ताओं के वकील।

श्री एस.पी. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एल.एस. सामंत और श्री द्वारा सहायता प्रदान की गई शरद शर्मा प्रतिवादियों के वकील हैं।

निर्णय

माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, जे.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत प्रस्तुत की जाने वाली यह अपील निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है और डिक्री दिनांक 13.10.1977, विद्वान III अपर जिला जज, सहारनपुर (पूर्व में हरिद्वार) द्वारा पारित सिविल अपील संख्या 117 में जिला सहारनपुर का हिस्सा था) 1976 और 1976 की सिविल अपील संख्या 118, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा मूल रूप से पारित निर्णय और डिक्री पार्टियों के बीच 1968 के मुकदमे संख्या 85 की पुष्टि की गई है।

2. वाद–विवाद का मामलाः– वाद पत्र के अनुसार महंत टहल दास महंत शोभा दास के चेला थे। वह किसका उदासीन था? पूज्य गुरु के ज्येष्ठ पुत्र पूज्य श्री चंद का पंथ नानक देव जी। उक्त पंथ में, एक रिवाज है कि महंत शादी नहीं कर सकता है और वह पहल करने का हकदार है (एक बनाने के लिए) एक चेला के साथ संबंध। और ऐसे की मृत्यु के बाद महंत, उनके सबसे बड़े चेला सभी अधिकारों के लिए सफल होते हैं और अपने गुरु की संपत्ति में रुचि। यह भी एक रिवाज है उपरोक्त पंथ कि गुरु की मृत्यु के दसवें दिन, गुरु का अखंड पाठ होने पर 'दशहरा' नामक एक समारोह होता है ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है और भोग लगाया जाता है। मृतक गुरु के सबसे बड़े चेला को किस रूप में स्वीकार किया जाता है? मृतक का उत्तराधिकारी जहां बाद में उसे महंत के नाम से जाना जाता है। महंत टहल दास ने

वादी– दूज दास को अपने रूप में शुरू किया सबसे बड़ा चेला असर सांबत की पूर्णिमा के दिन 1994 (यानी 23वां) जुलाई, 1937) भीटीवाला के डेरा में, तहसील– मुक्तसर, जिला फिरोजपुर, उपस्थिति में रिवाज के अनुसार वादी के सम्मानित व्यक्तियों और छोटी (टफ्ट) की संख्या महंत टहल दास द्वारा काटा गया था, और पवित्र मंत्र वादी के कानों में फुसफुसाया गया और वादी ने चरण मरई यानी पानी ले लिया जिससे गुरु के पैर धोए जाते हैं, जिसे भी जाना जाता है चरण घोल और एक लंगोट (काला) और भगवा के रूप में वादी को चादर (भगवा शीट) की पेशकश की गई थी जो इसे पहना। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। उस दिन, वादी महंत टहल दास का चेला बन गया और भीख मांगने के लिए यहां–वहां कस्टम के अनुसार भेजा जाता है। महंत टहल दास का 5 दिसंबर को भीटीवाला में निधन हो गया। 1957. उनका क्रिया–करम (अंतिम संस्कार) किसके द्वारा किया गया था? वादी अपने सबसे बड़े चेला के रूप में और दसवें दिन यानी दशहरा, गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ के बाद, प्रसाद कौन थे? वितरित। वादी को मान्यता दी गई थी और इसके बाद मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया और इसके बाद महंत दूज दास के नाम से जाना जाता है। जैसे, वह महंत के सभी अधिकारों, संपत्तियों और संपत्तियों को सफल बनाया तहल दास। इस बीच महंत टहल के निधन से पहले दास, प्रतिवादी प्राग दास, ईश्वर दास और हरि दास, उनके द्वारा चेलों के रूप में भी दीक्षित किया गया था। उसके पास कोई और नहीं था चेला (शिष्य) इन चारों को छोड़कर। महंत टहल दास भीटीवाला, शेखन, गोविंद में डेरे और संपत्तियां थीं गढ़, करारवाला, रामपुरा, धूरी और भूपतवाला (हरिद्वार)। सबसे बड़ा चेला होने के नाते वादी सभी सफल रहा ये गुण कस्टम के अनुसार हैं। बाहर महंत टहल दास को मिली संपत्ति कुछ भूमि पर पट्टा अधिकार उनके पक्ष में हस्तांतरित किए गए 18.03.1925. उन्हें 21 बीघा, 8 बिस्वा का भी तबादला किया गया खसरा प्लॉट संख्या 27 मीटर और 28 मीटर की कच्ची भूमि, कहाँ स्थित है? भूपतवाला कलां, हरिद्वार के एक श्री बीरबल शर्मा। उन्होंने कमरों, कोठारी का निर्माण किया और टिनशेड बनाए अच्छी तरह से खुदाई करने और एक तेल इंजन स्थापित करने के अलावा, उक्त भूमि पर ट्यूबवेल। महंत टहल दास को आगे मिला 1 बीघा, 3 बिस्वा और 10 बिस्वांसी का स्थायी पट्टा उसी गांव के खसरा प्लॉट नंबर 27 एम और 28 मीटर कहाँ से हैं? महंत साधु दास ने 17 अगस्त को लीज डीड के माध्यम सेकिया 1954(5 अगस्त, 1954 को पंजीकृत)। इसके बाद, 14 अप्रैल, 1955 के अन्यविलेख (29 तारीख को पंजीकृत) अप्रैल, 1955), और26 जून, 1955 (29 जून को पंजीकृत, 1955), खसरा प्लॉट नंबर 4 एम की 30

बीघा कच्ची जमीन मिली और महंत साधु से 19 बिगसा, 3 बिस्वा, 15 बिसवांसी सिंह। महंत टहल दास स्थायी पट्टेदार थे। उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था और भूमि प्राप्त कर रहा था अपने आदमियों और सेवकों की मदद से खेती की। उसने इस्तेमाल किया लगान का भुगतान भी किया। उपरोक्त पूरी भूमि का क्षेत्रफल इसमें दो भाग शामिल थे, एक हरिद्वार के पूर्व में–उक्त सड़क के पश्चिम में ऋषिकेश रोड और अन्य। वादी के अनुसार, उसे सात साल अखंड मिले करारवाला में वर्ष 1958 से 1965 तक किया गया पथ, भटिंडा और 12 अखोतारियों का अवलोकन किया (प्रत्येक अखोतरी लेता है) छह महीने)। इस बीच, उसे इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण, उसके द्वारा सफल। कब वादी 11 अप्रैल, 1968 को हरिद्वार आया था। अर्ध कुंभी, अपने गुरु की मृत्यु के बाद डुबकी लगाने के लिए पवित्र गंगा, उस दिन वह कुटिया (झोपड़ी) में रहने के लिए गया था अपने गुरु के। वहां अपनी यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि एक बुद्ध दास ने खुद को महंत का चेला बताया टहल दास ने बिक्री विलेख के माध्यम से अधिकार हस्तांतरित किए हैं दिनांक5 मई, 1962 (जून, 1962 को पंजीकृत) प्रतिवादी नंबर 1– उदासीन पंचायती बारा की संपत्ति अखाड़ा अपने महंत– प्रतिवादी नंबर 2– गोपाल दास के माध्यम से। वादी दूज दास ने बिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त की अप्रैल 1968 में कर्म और पाया कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2. बुद्ध दास के साथ मिलकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था उपरोक्त संपत्ति को वाद के अंत में वर्णित किया गया है। खास तौर पर मुकदमे में संपत्ति पर कब्जे की राहत की मांग करने से, वादी ने बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग की है उपरोक्त बिक्री विलेख को इस आधार पर चुनौती देना अर्थातः–

(a) बुद्ध दास को चेला के रूप में कभी नहीं माना गया था महंत टहल दास द्वारा।

(b) बुद्ध दास कभी भी संपत्ति में हक नहीं रखते हुए महंत टहल दास की तरफ थे।

(c) बुद्ध दास को वाद संपत्ति हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था।

(d) बिक्री विलेख में काल्पनिक रूप से प्रतिफल दर्शाया गया।

(e) विचाराधीन बिक्री विलेख मिलीभगत का परिणाम है बुद्ध दास और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के बीच, इस प्रकार वादी के लिए बाध्यकारी नहीं है।

3. <u>प्रतिवादियों द्वारा उनके मामले में मामला सेटअप</u>

<u>लिखित बयानः–</u>

प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने कथित तौर पर रिवाज से इन्कार किया वादी द्वारा।

इन प्रतिवादियों ने यह भी विवाद किया कि महंत टहल द्वारा वादी को कभी चेला के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था दास। उन्होंने महंत टहल दास का अंतिम संस्कार से भी वादी द्वारा इन्कार किया गया था। हालांकि, ये प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि महंत टहल दास की सम्पत्ति भीटीवाला, शेखान, गोविंद गढ़, करारवाला, रामपुरा और भूपतवाला (हरिद्वार) थी। यह भी स्वीकार किया कि महंत टहल दास की मृत्यु उसी वर्ष हुई थी 1957. लीज डीड्स का निष्पादन किसके पक्ष में किया गया? महंत टहल दास, जिनका उल्लेख वाद पत्र में किया गया है, भी हैं स्वीकार किया और यह विवादित नहीं है कि महंत टहल दास उल्लिखित भूमि के संबंध में एक स्थायी पट्टेदार था लीज डीड में। अतिरिक्त याचिकाओं में, ये प्रतिवादी अर्थात् दृ उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार (प्रतिवादी नंबर 1) और इसके महंत– गोपाल दास (प्रतिवादी नंबर 2) ने दलील दी है कि संपत्ति प्रश्न उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र जमींदारी द्वारा शासित है उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1956, और नागरिक अदालत के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। यह आगे दलील दी कि जवाब देने वाले प्रतिवादियों ने इसे खरीद लिया है विचार के लिए सूट में संपत्ति (रु. 32,000/–) बुद्ध दास से जिनकी मृत्यु लगभग तीन साल पहले हो चुकी है मुकदमे संस्थित करने की। इसमें आगे कहा गया है लिखित बयान में कि मृत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा क्या है? सुनवाई योग्य नहीं है (शुरू में बुद्ध दास को पक्षकार बनाया गया था) प्रतिवादी नंबर 3 के रूप में वाद–पत्र लेकिन बाद में उसका नाम था संशोधन के माध्यम से हटाया गया)। यह लिखित में आरोप लगाया गया है इन जवाब देने वाले प्रतिवादियों का बयान कि वादी– दूज दास मंगल दास का चेला है। यह बुद्ध दास था, टहल दास का चेला, जो कहाँ स्थित संपत्ति का उत्तराधिकारी बना अपने गुरु (महंत टहल) की मृत्यु पर भूपतवाला दास)। अंत में, यह दलील दी जाती है कि संविधान के अधिकार चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं को धारा 41 के तहत संरक्षित किया गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 में।

4. प्रतिवादी नंबर 5– हरि दास ने भी मुकदमा लड़ा अलग–अलग लिखित बयान दाखिल करके जिसमें केवल यह बहुत कुछ स्वीकार किया जाता है कि महंत टहल दास चेला थे महंत शोभा दास और पंथ के उदासीन थे गुरु नानक के बड़े पुत्र श्री चंद जी द्वारा सीापित देव जी। इस लिखित बयान में यह भी स्वीकार किया गया है कि महंत टहल दास के पास विभिन्न स्थानों पर संपत्तियां थीं। जिसमें विचाराधीन संपत्ति भी शामिल है। यह भी विवादित नहीं है कि महंत टहल दास की मृत्यु हो गई

है। अतिरिक्त याचिकाओं में, यह प्रतिवादी (जिसने गलत तरीके से अलग दूसरी अपील दायर की थी) 2001 के 1507 के रूप में क्रमांकित, 1977 का पुराना नंबर 2713, 16. 12.1996 को पहले ही वापस ले लिए गए के रूप में बर्खास्त कर दिया गया है) दलील दी कि वादी दूज दास मंगल दास का चेला है जो वास्तव में महंत टहल दास के शिष्य थे। यहन प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि बुद्ध दास (ट्रांसफरर) विवादित बिक्री विलेख) महंत टहल दास का चेला था जो मुकदमा शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। यह आगे दलील दी गई कि शुरू में बुद्ध दास को शामिल किया जाए (इसके बाद भी) उसकी मृत्यु) वाद में ही दर्शाता है कि वादी ने संबंध में विकास का कोई ज्ञान नहीं है महंत टहल दास की मृत्यु के बाद मुकदमे में संपत्ति का। प्रतिवादी नंबर 5 ने अपने लिखित बयान में आगे दलील दी महंत टहल दास के पास कई जगहों पर संपत्ति है लेकिन उनका मुख्यालय शेखान, तहसील बर्नल, संगरूर में था, पंजाब और हरिद्वार में स्थित संपत्ति की जांच की जा रही थी इसके बाद एक प्रेम दास ने। आरोप है कि प्रेम दास वास्तव में महंत तहल की मृत्यु के बाद महंत बने दास और उन्होंने बौद्ध दास को प्रबंधन के लिए नियुक्त किया हरिद्वार में सूट में संपत्ति। यह भी अनुरोध किया जाता है कि महंत टहल दास की मृत्यु का समय, बुद्ध दास तपस्या के लिए गए। अंत में, यह किसके द्वारा अनुरोध किया जाता है? प्रतिवादी नंबर 5 कि बुद्ध दास को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था मुकदमे में संपत्ति लेकिन चूंकि प्रेम दास को कोई आपत्ति नहीं थी इस पर किसी और को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

5. **<u>निर्विवाद तथ्यः–</u>** उपरोक्त दलीलों से, यह महंत टहल ने चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को स्वीकार किया है दास सूट में भूमि के संबंध में स्थायी पट्टेदार था। यह भी विवादित नहीं है कि महंत टहल दास की मृत्यु इसी राज्य में हुई थी। वर्ष 1957 में वर्ष 1925, 1951, 1954 और 1954 के पट्टा विलेख 1955, जिसे तहल दास के पक्ष में निष्पादित किया गया था, भी इसमें शामिल नहीं हैं प्रश्न। यह भी स्वीकार किया गया तथ्य है कि महंत टहल दास कई स्थानों पर स्वामित्व वाली संपत्तियां, अर्थात्– भीटीवाला, शेखान, गोविंद गढ़, करारवाला, रामपुरा, धूरी और भूपतवाला (हरिद्वार)। प्लॉट को लेकर कोई विवाद नहीं है। संख्याएं और मैदान में उल्लिखित भूमि के क्षेत्र।

6. **<u>ट्रायल कोर्ट द्वारा तैयार किए गए मुद्देः–</u>** ट्रायल कोर्ट परीक्षण के दौरान निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गएः दृ

1. *क्या उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों को देखते हुए जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1956 मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है?*
2. *क्या सूट का मूल्यांकन कम है? यदि हां, तो इसका प्रभाव?*
3. *क्या वादी को सबसे बड़े चेला के रूप में शुरू किया गया था महंत तेहल दास (मृतक) के अनुसार पैरा नंबर 1 और 2 में आरोप लगाया गया रिवाज सादा? यदि हां, तो इसका प्रभाव?*
4. *क्या वादी, सबसे बड़ा चेला होने के नाते, बन गया संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी महंत टहल दास? यदि हां, तो क्या वह इसके हकदार हैं? सूट में संपत्ति?*
5. *क्या बुद्ध दास संपत्ति के उत्तराधिकारी बने? महंत टहल के स्वामित्व वाले हरिद्वार में भूपतवाला दास और यदि हां, तो क्या वह स्थानांतरित करने के लिए सक्षम था? प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के मुकदमे में संपत्ति?*
6. *क्या श्री प्राग दास (प्रतिवादी संख्या 3) महंत टहल दास की संपत्ति में सफल शेखान, धूरी और गोविंद गढ़ में स्थित है?*
7. *क्या दिनांक 05.5.1962 का बिक्री विलेख किसके द्वारा निष्पादित किया गया है? प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के पक्ष में बुद्ध दास पैरा 11 में उल्लिखित आधारों पर शून्य है वाद? यदि हां, तो क्या वादी इसका हकदार है? विवाद में संपत्ति पर कब्जा, और क्या लाभ है?*
8. *वादी किस अनुतोष, यदि कोई हो, का हकदार है?*
9. *क्या प्रेम दास महंत के उत्तराधिकारी बने थे महंत टहल दास के अधिकार जैसा कि आरोप लगाया गया है प्रतिवादी नंबर 5? यदि हां, तो क्या महंत प्रेम दास ने पूरी गद्दी में अपने अधिकारों को त्याग दिया 11.08.1968 को प्रतिवादी संख्या 5 हरि के पक्ष में जैसा कि आरोप लगाया गया है?*
10. *क्या प्रेम दास ऐसा करने में सक्षम थे जैसा कि आरोप लगाया गया है, संपत्ति में अधिकारों को त्याग दें?*

7. **<u>निचली अपीलीय अदालत के समक्ष उठाए गए बिंदुः–</u>**

निम्नलिखित बिंदु उठाए गए और पहले बहस की गई अपीलकर्ताओं द्वारा निचली अपीलीय अदालतः–

1. *क्या वादी– दूज दास सबसे बड़ा है महंत टहल दास का चेला?*

2. *क्या वादी को विधिवत रूप से स्थापित किया गया था महंत टहल के स्थान पर उत्तराधिकारी महंत जैसा कि आरोप लगाया गया है?*
3. *क्या प्रेम दास महंत के उत्तराधिकारी थे क्या आप जानते हैं?*
4. *क्या प्रेम दास ने किसके पद का पालन किया था? हरि दास के पक्ष में महंतत्व?*
5. *क्या बुद्ध दास (स्थानांतरणकर्ता) स्थापित किया गया था महंत टहल दास के उत्तराधिकारी के रूप में हरिद्वार में संपत्ति क्या है?*
6. *क्या प्रतिवादी नंबर 1 और 2 प्रामाणिक हैं विचार के लिए खरीदार? यदि हां, तो इसका प्रभाव?*
7. *क्या मुकदमा एक सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञेय नहीं है?*
8. *क्या वादी किसी भी राशि का मेंसप्रोफिट प्राप्त करने हकदार है?*

9. <u>नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्ष/निर्णयः</u>

निचली अदालत द्वारा तैयार किए गए मुद्दे नंबर 1 और 2 थे 13.10.1969 को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय लिया गया। यह प्रासंगिक है यहां उल्लेख करना था कि क्षेत्राधिकार के बिंदु पर मुद्दा क्या था? ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। जैसा कि मूल्यांकन, मुद्दा यह मानते हुए तय किया गया था कि मूल्य संपत्ति की कीमत 10,389 रुपये है। ऐसा प्रतीत होता है कि नतीजतन आवश्यक संशोधन किए गए और निचली अदालत के समक्ष अदालत की फीस का भुगतान किया गया था।

9. साक्ष्य दर्ज करने के बाद, मुद्दे संख्या 3 के रूप में और पक्षकारों को सुनकर, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि दूज दास महंत टहल दास के सबसे बड़े चेला थे। पर मुद्दा संख्या 4, 5 और 6, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि यह वादी था जो मुकदमे में संपत्ति में सफल रहा था तहल दास ने अपनी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। यह आगे परीक्षण द्वारा आयोजित किया गया था अदालत ने कहा कि बुद्ध दास को सम्पत्ति स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को। ये आगे कहा गया कि प्राग दास ने कभी भी संपत्ति यों को सफल नहीं किया तहल दास से। मुद्दे संख्या 7 पर, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि दिनांक 05.05.1962 का बिक्री विलेख, विचाराधीन, एक जाली है और काल्पनिक दस्तावेज और उस पर कोई उपाधि प्रदान नहीं की प्रतिवादी नंबर 1 और 2। मुद्दे नंबर 9 और 10 भी थे प्रतिवादियों के खिलाफ

फैसला किया। और उस वादी को पकड़ना कब्जे की राहत के साथ–साथ राहत का हकदार है बिक्री विलेख को रद्द करना, मुकदमा तय किया गया था तदनुसार, रु. 500/– प्रति माह मेन्सप्रोफिट के साथ।

10. विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने भी फैसला सुनाया इसके सामने उठाए गए बिंदु, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसके पक्ष में है? वादी (इस अदालत के समक्ष प्रतिवादी), और सहमत ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष के साथ। व्यथित दिनांक 13.10.1977 के निर्णय और डिक्री द्वारा पारित निचली अपीलीय अदालत, जिसके द्वारा स्थापित अपील हरि दास (1976 की सिविल अपील संख्या 117), और उदासीन पंचायती बाड़ा अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार और इसके महंत गोपाल दास (1976 की सिविल अपील संख्या 118) थे वर्ष 1977 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता दी गई जहां से इसके प्रवेश के बाद, यह अपील किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 35 के तहत यह न्यायालय, 2000, इसके निपटान के लिए। (द्वितीय अपील संख्या 2713) 1997 हरि दास द्वारा दायर याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था 16.12.1996 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा)

11. **<u>इसमें शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न मामलाः–</u>**

कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं इस अपील मेंः–

1. *क्या उत्तर प्रदेश शहरी के प्रवर्तन के बाद क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1956, वाद में भूमि, निम्नलिखित में निहित थीः कानून के संचालन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सभी से मुक्त बोझ और उसके साथ खड़े हो गए अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1 और 2) विशेष रूप से? यदि हां, तो क्या मुकदमा धारा 331 द्वारा प्रतिबंधित किया गया था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950?*
2. *क्या मुकदमा सीमा के कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और क्या सीमा की दलील उठाई जा सकती है ऐसी स्थिति में दूसरी अपील के चरण में जब न तो इसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष दबाया गया था और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष?*
3. *क्या उत्तर प्रदेश राज्य और गांव सभाधगांव पंचायत, आवश्यक पक्षकार*

थे? यदि हां, तो क्या मुकदमा खारिज होने योग्य था? आवश्यक दलों के शामिल न होने के लिए?

12. कानून के उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रश्न थेः इस न्यायालय द्वारा केवल 12.11.2002 को तैयार किया गया था, जैसा कि यह प्रतीत होता है कि असावधानी के कारण इसे किसके द्वारा तैयार नहीं किया जा सका? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भर्ती के समय वर्ष 1977 में अपील। यहां उल्लेख करना उचित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100, 01.02.1977 से संशोधित किया गया था, और इसका ज्ञापन नवंबर 1977 में प्रस्तुत अपील में शामिल नहीं है हालांकि आधार के आधार पर कानून के पर्याप्त प्रश्न सुझाए गए अपील में उल्लिखित उपरोक्त प्रश्न उठाए गए थे।

13. **<u>कानून संख्या 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तरः–</u>**

श्री अजीत कुमार, अपीलकर्ताओं के वकील प्रस्तुत किया कि चूंकि कब्जे के लिए राहत के संबंध में कृषि क्षेत्र, नगर पालिका की सीमा के भीतर है, जो क्या हो सकता? राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय है। प्रश्नगत वाद सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञेय नहीं है। यह उल्लेख करना उचित है यहां उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1956 (1957 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या IX) को यह अधिनियम मिला 7 मार्च, 1957 को राष्ट्रपति की सहमति और उत्तर प्रदेश राजपत्र में दिनांक 12तारीख को प्रकाशित मार्च, 1957। उक्त अधिनियम को प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था कृषि क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में और अधिग्रहण के लिए अधिकार शीर्षक और मध्यस्थों के बीच रुचि मिट्टी और राज्य की जुताई। उक्त उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 8 1957 की सं. IX निम्नानुसार हैः–

''8. **राज्य में कृषि क्षेत्र का निहितीकरणः–** धारा 5 के तहत कृषि क्षेत्र का सीमांकन किया गया है, राज्य सरकार, किसी भी समय, अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र, इसे एक तारीख से घोषित करता है शहरी क्षेत्र में स्थित ऐसे सभी क्षेत्र निर्दिष्ट किए जाएंगे राज्य में निहित है और, तारीख की शुरुआत से निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे सभी कृषि क्षेत्र खड़े होंगे यहाँ दिए गए को छोड़कर यहाँ स्थानांतरित और बनियान में, राज्य सभी दायित्वों से मुक्त है। 20 जून, 1963 की एक अधिसूचना संख्या 2653/1–ए–168–60 उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित, भाग 1 दिनांक 29 जून, 1963 पृष्ठ 1217 से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में गिरावट आ रही है हरिद्वार नगरपालिका,

1 जुलाई से उत्तर प्रदेश राज्य में निहित है, 1963. अधिसूचना के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत किया गया है नीचेः–''

'' राजस्व विभाग अधिसूचना संख्या 2653/1–ए–168–60,

दिनांक 20 जून, 1963, उत्तर प्रदेश राजपत्र भाग I में प्रकाशित

दिनांक 29 जून 1963, पृष्ठ 1217.

उत्तर प्रदेश के लिए धारा 8 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1956 (1957 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या IX), उत्तर प्रदेश के राज्यपाल प्रदेश को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह किसके पहले दिन से है? जुलाई, 1963, निम्नलिखित शहरी क्षेत्रों में सभी कृषि क्षेत्र राज्य के क्षेत्र, जिनका इस प्रकार सीमांकन किया गया है उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 किस राज्य में निहित होगी? उत्तर प्रदेश, और उस तारीख की शुरुआत से, इस तरह के सभी कृषि क्षेत्रों को हस्तांतरित किया जाएगा, और बनियान, राज्य में उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधान के अलावा, सभी दायित्व

सीरियल नंबर	शहरी क्षेत्र का नाम	जिला
	मेरठ मंडल	
	नगरपालिका	
1..	.....	.....
2. हरिद्वार संयोग	दो	सहारनपुर
3.....	.....	.....

राजपत्र में प्रकाशित पूर्वोक्त अधिसूचना क्या हो सकती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 81 के तहत अदालत द्वारा पढ़ा गया वादी/प्रतिवादी की ओर से, यह है तर्क दिया कि सीमांकन के बिना, निहित नहीं हो सकता है नगरपालिका की सीमा के भीतर कृषि क्षेत्र। हालांकि, इस न्यायालय की राय है कि अभिव्यक्ति ''जिसे इस प्रकार सीमांकित किया गया है'' अधिसूचना में निहित उपर्युक्त अधिनियम के लिए धारा 5, स्वयं इंगित करता है कि सीमांकन इससे पहले किया गया था उत्तर प्रदेश अधिनियम IX की धारा 8 के तहत पूर्वोक्त अधिसूचना 1957 में जारी किया गया था। यह भी याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया जाता है वादी/प्रतिवादी कि सीमांकन के

संबंध में, न तो मामले में कोई दलील या सबूत नहीं है। लेकिन अदालत यह पाया गया कि यह लिखित बयानों में कहा गया है प्रतिवादी नंबर 1 और 2, विशेष रूप से अतिरिक्त याचिकाओं में कि विवाद में संपत्ति राजस्व भुगतान भूमि है और यह उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र जमींदारी द्वारा कवर और शासित है उत्सादन भूमि सुधार अधिनियम, 1956 अदालत के पास मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह दलील है इस मुद्दे को उठाने के लिए पर्याप्त है कि भूमि कैसे विचाराधीन है राज्य में निहित था। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि कानून और साक्ष्य की पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है। उस ऐसा होने के नाते, उपरोक्त अधिसूचना के तहत, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है हरिद्वार नगर पालिका में वह कृषि भूमि, किसमें निहित है? 1 जुलाई, 1963 से राज्य, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है पूर्वोक्त अधिसूचना।

14. यह वादी/प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया जाता है कि सूट में संपत्ति में भवन, ट्यूबवेल शामिल है, ईंट–भट्ठा इस प्रकार, संपत्ति को नहीं कहा जा सकता है कृषि क्षेत्र। विवाद की जांच करने के लिए, यह है इस बिंदु पर कानून के प्रावधानों को देखना आवश्यक है। अभिव्यक्ति 'कृषि क्षेत्र' को धारा 2 (1) में परिभाषित किया गया है उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1956 और उसमें निहित परिभाषा, निम्नानुसार पढ़ें: –

''(1) किसी भी शहरी क्षेत्र के संबंध में 'कृषि क्षेत्र' उसका अर्थ उस क्षेत्र से होता है, जो इस प्रकार की तारीख के संदर्भ में होता है। राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है,

(a) कब्जे में या आयोजित या माना जाता है सर, खुदकाश्त या एक मध्यसि के रूप में एक मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थ का उपवनय

(b) व्यक्तिगत खेती द्वारा या उसमें एक उपवन के रूप में आयोजित अवध में एक स्थायी पट्टेदारय नहीं तो

(c) होल्डिंग में शामिल–

(i) एक निश्चित दर किरायेदार,

(ii) एक पूर्व–मालिकाना किरायेदार,

(iii) अधिभोग किरायेदार,

(iv) एक किरायेदार जो विशेष शर्तों पर धारण करता है अवध,

(v) किराया–मुक्त अनुदानदाता,

(vi) अनुकूल किराये की दर पर अनुदानग्राही,

(vii) एक वंशानुगत किरायेदार,

(viii) एक उपवन धारक,

(ix) उप–धारा (4) में निर्दिष्ट उप–किरायेदार उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम की धारा 47 1939, या

(x) इसके अलावा अन्य भूमि का गैर–अधिभोग किरायेदार भूमि की उपधारा (3) में उल्लिखित भूमि उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम, 1939 के लिए धारा 30य और इसके धारक द्वारा इसके लिए उपयोग किया जाता है कृषि या बागवानी के प्रयोजनय हमेशा वह भूमि प्रदान करें जो तारीख पर हो

पूर्वोक्त इमारतों द्वारा कब्जा नहीं किया गया है अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित ''सुधार'' उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम, 1939, और भूमि अधिग्रहण ऐसी इमारतों को नहीं माना जाएगा कृषि क्षेत्र।

(d) पहले दिन से पहले विधिवत निष्पादित पट्टे पर रखा गया जुलाई, 1955 को खड़ा करने के प्रयोजनों के लिए उस पर इमारतें, या

(d) एक कब्जाधारी द्वारा आयोजित या कब्जा कर लिया गया:

व्याख्या– एक क्षेत्र, जो किसी क्षेत्र की होल्डिंग का हिस्सा है किरायेदार को यह नहीं माना जाएगा कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है कृषि क्षेत्र केवल इस कारण से कि यह नहीं है पिछले सात वर्षों के दौरान उपयोग किया गया फसलों या अन्य को उगाने के लिए इस अधिनियम का प्रारंभ कृषि उत्पाद।

'होल्डिंग' शब्द के अर्थ के रूप में उप–धारा धारा 2 का (16) स्पष्ट करता है कि इसका एक ही अर्थ होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम, 1939 में निहित है। उपधारा (7) उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम, 1939 की धारा 3, शब्द को परिभाषित करती है 'पकड़ना' और निम्नानुसार पढ़ता हैः दृ

''(8) ' होल्डिंग' का अर्थ है भूमि का एक पार्सल या पार्सल एक पट्टे के तहत, सगाई या अनुदान, या अनुपस्थिति में एक कार्यकाल के तहत ऐसे पट्टे, सगाई या अनुदान की राशि और एक ठेकेदार के मामले में ठेका क्षेत्र शामिल है।''

वाद पत्र के पैरा –10 में, वादी ने स्पष्ट रूप से दलील दी कि वह सभी भूमि का स्थायी पट्टेदार है पूर्वोक्त पट्टा। इसके अलावा पैरा–6 और 7 में वाद–विवाद में यह दलील दी गई है कि महंत टहल दास उल्लिखित पट्टा विलेख के माध्यम से स्थायी पट्टेदार था इन पैरा में जिनसे वादी ने दावा किया विरासत। इतना ही नहीं, वाद–पत्र

के पैरा–8 में विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि महंत टहल दास थे अपने आदमियों और सेवकों के माध्यम से भूमि पर खेती कर रहे हैं। जैसा जैसे, केवल तथ्य यह है कि कमरे, ट्यूब–वेल, टिन–शेड हैं, विचाराधीन भूमि में स्थित, इसकी प्रकृति को नहीं बदलता है ''कृषि क्षेत्र'' से। हालांकि, ईंट–भट्ठा निश्चित रूप से एक सुधार नहीं कहा जा सकता है जो एक का निर्माण कर सकता है कृषि क्षेत्र का हिस्सा लेकिन बाकी भूमि नहीं है इसके चरित्र को बदल दिया (हालांकि, यह वह जगह नहीं है जहां अनुरोध किया गया था ईंट–भट्ठा महंत टहल दास द्वारा स्थापित किया गया था)। 'सुधार' शब्द को धारा 3 (8) के तहत परिभाषित किया गया है उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम, 1939, जो निम्नानुसार हैः –

''(8) *'सुधार', का अर्थ किरायेदारों के संदर्भ में है पकड़ः–*

(i) *व्यक्ति द्वारा धारित मकान पर बनाया गया आवास–गृह किरायेदार अपने स्वयं के व्यवसाय या पशु शेड के लिए या एक स्टोर–हाउस या किसी अन्य निर्माण के लिए उसके द्वारा सृजित या स्थापित किया गया कृषि प्रयोजन या उसकी पकड़।*

(ii) *कोई भी कार्य जो भौतिक रूप से किसके मूल्य को जोड़ता है? होल्डिंग और उद्देश्य के अनुरूप है, जिसके लिए इसे अनुमति दी गई थी, और जो, यदि निष्पादित नहीं किया गया था होल्डिंग पर, या तो इसके लिए सीधे निष्पादित किया जाता है लाभ या निष्पादन के बाद सीधे किया जाता है इसके लिए फायदेमंदय और पूर्वगामी के अधीन इस खंड के प्रावधानों में शामिल हैंः*

- *(a) कुओं, जल चौनलों का निर्माण और आपूर्ति के लिए अन्य कार्य या कृषि के लिए पानी का वितरण प्रयोजनोंय*
- *(b) इन परियोजनाओं के लिए कितने कार्य किए गए हैं? भूमि की जल निकासी, या सुरक्षा के लिए बाढ़ से, या कटाव से भूमि की संख्या या पानी से अन्य नुकसानय*
- *(c) समाशोधन, संलग्न, समतलीकरण या भूमि की चोरीय*
- *(d) नदी के निकटतम क्षेत्र में निर्माण गाँव की तुलना में अन्यथा पकड़ साइट, इमारतों के लिए आवश्यक इमारतों की साइट सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग या होल्डिंग का व्यवसायः*
- *(e) टैंकों का निर्माण या अन्य कार्य कृषि प्रयोजनों के लिए पानी का भंडारणय*
- *(f) इनमें से किसी का नवीकरण या पुननर्माण पूर्वगामी कार्य, या इस तरह के परिवर्तन इसमें, या उसमें परिवर्धन, जैसा कि नहीं है केवल मरम्मत*

की प्रकृतिः

बशर्ते कि ऐसे पानी के चौनल, तटबंध, बाड़े, अस्थायी कुएं, या अन्य कार्य किरायेदारों द्वारा सामान्य रूप से किए जाते हैं खेती के पाठ्यक्रम को नहीं माना जाएगा सुधार।

अभिव्यक्ति की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए ''कृषि'' क्षेत्रः ''होल्डिंग'' की परिभाषा के साथ पढ़ें और ''सुधार'' और ऊपर उद्धृत अधिसूचना, यह है पूरी तरह से स्पष्ट है कि सूट में भूमि वास्तव में किसमें निहित है, 1 जुलाई, 1963 से राज्य में। इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए कानून में गलती की है कि मुकदमा सिविल कोर्ट द्वारा संज्ञेय है। निचली अपीलीय अदालत ने भी इसी दृष्टिकोण की पुष्टि करके कानून में गलती की है।

15. वादी/प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील, प्रस्तुत किया कि मुकदमे में मुख्य राहत रद्द करने के लिए है बिक्री विलेख, जिसे सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता था राजस्व न्यायालय, इस प्रकार, नीचे की अदालतों ने नहीं किया है सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए कानून की कोई गलती की है कि मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र। यह उल्लेख करना उचित है यहां कि मुकदमा शुरू में वादी द्वारा स्थापित किया गया, केवल कब्जे के लिए और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, राहत बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए जोड़ा गया था। धारा 82 उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1956 (1957 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या IX) निम्नलिखित के प्रावधान करता हैः उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की धारा 331, 331 ए और 333 और भूमि सुधार अधिनियम, 1950, मुकदमों पर लागू होता है और 1956 के अधिनियम संख्या IX के तहत कार्यवाही)। धारा 331 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950, निम्नानुसार हैः –

*''331. **मुकदमों का संज्ञान, आदि। इस अधिनियम के तहत–(1)** इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत किए गए प्रावधान के अलावा कोई अन्य अदालत नहीं है अनुसूची II के कॉलम 4 में उल्लिखित अदालत की तुलना में, सिविल में निहित किसी भी चीज के बावजूद प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V), की मान्यता लें कॉलम में उल्लिखित कोई मुकदमा, आवेदन या कार्यवाही 3. या उसके आधार पर एक मुकदमा, आवेदन या कार्यवाही कार्रवाई का एक कारण जिसके संबंध में कोई राहत हो सकती है ऐसे किसी भी मुकदमे या आवेदन के माध्यम से प्राप्तः*

बशर्ते कि जहां एक घोषणा की गई है धारा 143 के तहत किसी भी होल्डिंग

या भाग के संबंध में इसके बारे में, अनुसूची II के प्रावधान, जहां तक वे हैं अध्याय के तहत मुकदमों, आवेदनों या कार्यवाही से संबंधित VIII ऐसी होल्डिंग या उसके भाग पर लागू नहीं होगा।

व्याख्या– यदि कार्रवाई का कारण निम्नलिखित में से किसके संबंध में है?
राजस्व न्यायालय द्वारा कौन सी राहत दी जा सकती है, यह है
सिविल कोर्ट से मांगी गई राहत का कोई मतलब नहीं
हो सकता है कि राजस्व न्यायालय के समान न हो।
अनुमति दे दी होगी।

(1–A) *उपधारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, आपत्ति है कि एक अदालत ने अनुसूची के कॉलम 4 में उल्लेख किया है II, या, जैसा भी मामला हो, एक सिविल कोर्ट, जिसका कोई नहीं था वाद, आवेदन के संबंध में क्षेत्राधिकार या कार्यवाही, उसके संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा अदालत जब तक कि आपत्ति पहले की अदालत में नहीं ली गई थी उदाहरण के लिए जल्द से जल्द संभव अवसर और सभी में ऐसे मामले जहां मुद्दे का निपटान किया जाता है, ऐसे निपटान पर या उससे पहले, और जब तक न्याय की विफलता नहीं हुई है।*

(2) इसके बाद की शर्त के बिना अपील की जाएगी किसी भी के तहत पारित आदेश या डिक्री से झूठ बोलना के कॉलम 3 में उल्लिखित कार्यवाही उपरोक्त अनुसूचीः

(3) अपील किसी डिक्री से या किसी डिक्री से होगी। धारा 47 या आदेश के तहत पारित आदेश संहिता की धारा 104 में उल्लिखित प्रकृति सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का V) या क्रम में XLIII, उस कोड की पहली अनुसूची का नियम 1 कॉलम नंबर 4 में उल्लिखित एक अदालत द्वारा पारित इस अधिनियम की अनुसूची ॅ का उल्लेख कार्यवाही में किया गया है इसके कॉलम नंबर 3 में अदालत या प्राधिकरण को इसके कॉलम नंबर 5 में उल्लेख किया गया है।

(4) दूसरी अपील किसी भी आधार पर निहित होगी सिविल संहिता की धारा 100 में निर्दिष्ट प्रक्रिया, 1908 (1908 का V) अंतिम आदेश से या डिक्री, उप–धारा के तहत अपील में पारित (3) प्राधिकरण के लिए, यदि कोई हो, तो उसके विरुद्ध उल्लिखित उपरोक्त अनुसूची के कॉलम 6 में। ''

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की द्वितीय अनुसूची के लिए क्रम संख्या 24 और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 जो निष्कासन के लिए उपयुक्त प्रावधान करता है बिना मालिकाना हक के भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को सहायक के समक्ष रखा जाएगा कलेक्टर प्रथम श्रेणी (यानी राजस्व न्यायालय), यहाँ उद्धृत किया गया है नीचेः–

क्रम संख्या	धारा	कार्यवाही का विवरण	न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार	न्यायालय	
				पहला अपील	द्वितीय अपील
24	209	मुकदमा का निष्कासन व्यक्तियों कब्जा करना बिना भूमि के शीर्षक और क्षतिपूर्ति के लिए	सहायक कलेक्टर प्रथम वर्ग	कमिश्नर तख्ता	

इस प्रकार, उपरोक्त प्रविष्टि की दूसरी अनुसूची में निहित है उपरोक्त अधिनियम, ऊपर उद्धृत धारा 331 के साथ पढ़ा जाता है, मुकदमे के संबंध में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है कृषि भूमि के कब्जे में।

16. श्री एस.पी.गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने बहस की। वादी/प्रतिवादी की ओर से कि चूंकि मुकदमा मूल रूप से किसके लिए है? बिक्री विलेख को रद्द करना, जिसे सिविल द्वारा प्रदान किया जा सकता है इस प्रकार, कब्जे के लिए मुकदमा भी अदालत के समक्ष होगा। सिविल कोर्ट। निवेदन के समर्थन में, याचिकाकर्ता की ओर से वादी/प्रतिवादी के वकील, इस पर ध्यान दें न्यायालय श्रीमती मेनका गांधी में निहित कानून के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुआ। **बिस्मिल्लाह बनाम जनेश्वर प्रसाद (1990) एस.सी.सी. 207** उक्त मामले के कानून के पैरा 7 में निम्नानुसार लिखा हैः–

''यह स्थापित कानून है कि अधिकार क्षेत्र का बहिष्करण सिविल कोर्ट का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है बहिष्करण या तो स्पष्ट रूप से

व्यक्त किया जाना चाहिए या स्पष्ट रूप से निहित। कानून के प्रावधान जो इसे हटाने की कोशिश करते हैं सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सख्ती से समझने की जरूरत है। अधिनियम की धारा 331 किसकी श्रृंखला का विषय रही है? उच्च न्यायालय की घोषणाएं परिस्थितियां और मुकदमों की प्रकृति जिसमें यह है बहिष्करण प्रभाव संचालित होता है। भेद की मांग की गई थी उन मामलों के वर्ग के बीच खींचा गया जहां बाध्यकारी प्रभाव एक कार्य को एक उपयुक्त व्यक्ति द्वारा छुटकारा पाना था एक तरफ निर्णय और मामलों का वर्ग जिसे कानून में शून्य कहा जा सकता है जहां एक लेनदेन

कानून जो शून्य मानता है, उसे रद्द करने के लिए कुछ भी नहीं है या दूसरे पर अलग रख दें। पूर्व मामले में, यह आयोजित किया गया था, एक मुकदमा सिविल कोर्ट द्वारा संज्ञेय था, जबकि बाद में, ऐसा नहीं था, यह वैधानिक प्राधिकरण के लिए खुला था उन कानूनी घटनाओं पर ध्यान दें जो कोई घोंसला नहीं था।''

उपरोक्त से जो प्रतीत होता है वह यह है कि शून्य दस्तावेज, राजस्व न्यायालय का अधिकार क्षेत्र शून्य के मामले में अप्रभावित रहता है दस्तावेज, अधिकार क्षेत्र सिविल कोर्ट में होगा। यह यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान मामले में, वादी उस मामले के साथ आया है जो बुद्ध दास के पास है कोई अधिकारी भूमि को हस्तांतरित करने के लिए ऐसा नहीं है जैसा कि उसने कभी नहीं किया इसमें सफलता मिली। दूसरे शब्दों में, उन्होंने उस बिक्री विलेख का अनुरोध किया प्रश्न एक गैर–दस्तावेज है।

17. बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए एक मुकदमा निम्नानुसार हैः विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 31, जो निम्नानुसार हैः–

''31. जब रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है – *(1) कोई भी व्यक्ति जिनके खिलाफ एक लिखित दस्तावेज शून्य या शून्य है, और किसे उचित आशंका है कि ऐसा साधन। यदि उत्कृष्ट छोड़ दिया जाता है। वह गंभीर हो सकता है चोट, इसे शून्य या शून्य घोषित करने के लिए मुकदमा कर सकती है, और न्यायालय अपने विवेकाधिकार से इसका निर्णय ले सकता है और आदेश दे सकता है। वितरित किया जाना चाहिए और रद्द कर दिया जाना चाहिए।*

(2) यदि लिखत के तहत पंजीकृत किया गया है भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), न्यायालय इसके फरमान की एक प्रति उस कार्यालय को भी भेजें जिसके कार्यालय में उपकरण को इस तरह पंजीकृत किया गया हैय और ऐसे

अधिकारी उसके में निहित उपकरण की प्रति पर नोट करेगा किताबें इसके रद्द होने के तथ्य को उजागर करती हैं।

दोनों पक्षों की ओर से इसमें रिलायंस रखी गई। ***इंद्र देव और अन्य बनाम श्रीमती राम प्यारी और एक और 1982 सब। एल.जे. 1308*** जिसमें लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है किः–

''उन्होंने कहा, 'निर्णायक बात कार्रवाई का कारण है जिस पर कार्यवाही आधारित है। कार्रवाई के इस कारण के संबंध में राजस्व न्यायालय राहत देने के लिए सक्षम है, मुकदमा या कार्यवाही राजस्व न्यायालय में होगी न कि न्यायालय में। सिविल कोर्ट, धारा 331 के तहत अधिकार क्षेत्र अनन्य है और समवर्ती नहीं। इसलिए, यदि इसके आधार पर वाद में दी गई कार्रवाई का कारण संज्ञेय है राजस्व न्यायालय द्वारा, अकेले राजस्व न्यायालय के पास होगा उसी पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र और सिविल कोर्ट मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सामग्री इसलिए, दृढ़ संकल्प के लिए कारण क्या है बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए वाद में कार्रवाई इस आधार पर कि विलेख के निष्पादक के पास कोई शीर्षक नहीं था विलेख के माध्यम से बताई गई संपत्ति? क्या यह किसका दावा है? निष्पादनकर्ता द्वारा शीर्षक जिसमें इनकार शामिल है वादी का शीर्षक विलेख का निष्पादन है स्वयं?

इस न्यायालय की राय में, उपर्युक्त इंद्र देव का मामला, स्पष्ट रूप से सीमांकित करता है कि कब अधिकार क्षेत्र है राजस्व न्यायालय समाप्त हो जाता है और जब यह निहित होता है सिविल कोर्ट में। उदाहरण के लिए, यदि हस्तांतरणकर्ता ने मना कर दिया है भूमि को हस्तांतरित करके वादी का शीर्षक वास्तविक प्रश्न है जिसके लिए निर्णय लिया जाना है अधिकार क्षेत्र राजस्व न्यायालय के पास है। और अगर कुछ बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए वादी पर धोखाधड़ी की गई और उनके शीर्षक पर सवाल नहीं उठाया जाता है, रद्द करने के लिए एक मुकदमा दायर किया जाता है इस तरह के साधन केवल सिविल कोर्ट में होंगे। पार्टियों की दलीलों से, यह स्पष्ट है कि निष्पादन द्वारा वादी के बिक्री विलेख शीर्षक से इनकार कर दिया गया है हस्तांतरणकर्ता– बुद्ध दास, जैसा कि वर्तमान मामले में यह है कृषि भूमि के संबंध में शीर्षक का प्रश्न, जो वास्तविक मुद्दा है और ऐसे कारण के संबंध में, अधिकार क्षेत्र केवल राजस्व न्यायालय के पास है।

18. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय में ***राम पदारथ बनाम द्वितीय अपर जिला, सुल्तानपुर 1989 राजस्व निर्णय पृष्ठ 21,*** यह माना गया है किः–

''यह वास्तविक 'कार्रवाई का कारण' है जो निर्धारित करता है विशेष कार्रवाई पर विचार करने के लिए अदालत का अधिकार क्षेत्र वाद या पत्र में प्रयुक्त भाषा के बावजूद राहत का दावा किया। वह ताकत जिस पर वादी आता है अदालत बचाव या राहत पर निर्भर नहीं करती है दावे का मनोरंजन और राहत प्रदान करना। यह पिथ है और पदार्थ जिसे देखा जाना चाहिए, न कि भाषा जिसका उपयोग लोगों को बाहर निकालने के लिए भी किया गया हो सकता है एक विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र।''

19. राम पदरथ के मामले (सुप्रा) में, यह आगे है देखा किः—

''शून्य दस्तावेजों के संबंध में कार्रवाई के लिए मंच या कृषि भूमि के संबंध में उपकरण किस पर निर्भर करते हैं? तथ्यों के संदर्भ में कार्रवाई का वास्तविक कारण। शून्य दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है जैसे शून्य योग्य दस्तावेज। रद्द करने के लिए एक साधारण मुकदमा एक दस्तावेज या उपकरण यदि वही किसी के शरीर पर बादल डालता है दायां और शीर्षक या उस पर बादल डालने या प्रभावित करने की संभावना है कृषि संपत्ति के संबंध में भी प्रतिकूल रूप से, यह 'भूमि' है, इससे कोई कठिनाई नहीं होती है, बशर्ते कि यह आगे हो। दावेदार के अधिकार के बारे में किसी भी घोषणा की आवश्यकता नहीं है और भूमि पर स्वामित्व यानी किरायेदारी के अधिकार मौजूदा कानून।''

उपरोक्त टिप्पणियों ने यह सरल और स्पष्ट कर दिया था कि यदि वादी को किसके संबंध में अपना शीर्षक साबित करना आवश्यक है? कृषि भूमि तब केवल मुकदमा दायर करने की संस्था द्वारा रद्दीकरण, अधिकार क्षेत्र सिविल में निहित नहीं होगा न्यायालय में **(राम अवलंभ बनाम जटा शंकर और अन्य में) 1968 राजस्व निर्णय 740,** एक और पूर्ण पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पहले इसी तरह की बात कही थी देखें)।

20. क्या यह एक ऐसा मामला था जिसमें वादी दूज दास विचाराधीन संपत्ति का एक रिकॉर्ड किया गया कार्यकाल धारक था, यह आसानी से कहा जा सकता था कि मुकदमा रद्द करने के लिए बिक्री विलेख सिविल कोर्ट द्वारा संज्ञेय है, क्योंकि यह नहीं होगा शीर्षक की घोषणा शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य से, यह है ऐसा नहीं है। बल्कि वर्ष की वार्षिक खतौनी के लिए कॉपी करें 1375 फासली (कैलेंडर वर्ष 1967), जो पेपर नंबर 44 सी है ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में 1 (Exh-A-1) से पता चलता है कि यह प्रतिवादी नंबर 1 और 2 हैं, जो रिकॉर्ड किए गए कार्यकाल धारक हैं सूट में भूमि के संबंध में। इतना ही नहीं, तीन साल वर्ष 1374 से 1376 (कैलेंडर वर्ष 1966 से 1966)

के लिए खतौनी 1968), जिसकी एक प्रति पेपर नंबर 45 सी (Exh-A-2) है। भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वह भूमि जो मूल रूप से वह बीरबल शर्मा का था जिसके द्वारा एक विलेख निष्पादित किया गया था टहल दास के पक्ष में, किसके नाम पर उत्परिवर्तित किया गया है? प्रतिवादी नंबर 1 और 2। मैंने इसकी कॉपी की भी जांच की है। वर्ष 1366 फासली (कैलेंडर वर्ष 1958) का खतौनी, जो पेपर नंबर 82 सी (Exh-A-3) है। ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह बुद्ध दास हैं, जो विचाराधीन संपत्ति में कार्यकाल धारक के रूप में दर्ज किया गया। जैसा इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि वास्तविक प्रश्न पार्टियों के बीच शीर्षक का सवाल किसके संबंध में है? कृषि क्षेत्र, उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1956, जिसके लिए उपाय राजस्व न्यायालय में उपलब्ध था। और ट्रायल कोर्ट गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, जिसने किया उक्त अदालत में निहित नहीं है। और विद्वान निचले अपीलीय अदालत ने डिक्री की पुष्टि करके कानून में भी गलती की है ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित।

21. श्री गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने बहस की। वादी/प्रतिवादी कि धारा की उप–धारा (1–A) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 331 1950, अपवाद प्रदान करता है और अधिकार क्षेत्र को बचाता है सिविल कोर्ट द्वारा प्रयोग किया जाता है यदि इसे चुनौती नहीं दी जाती है पहली बार अदालत में। यह तर्क, में इस न्यायालय की राय, मदद नहीं करती है वादी/प्रतिवादी इस कारण से कि मैं पहले ही कर चुका हूं ऊपर चर्चा की गई है कि न केवल दलील लिखित बयान में क्षेत्राधिकार उठाया गया था, लेकिन एक इस मुद्दे को ट्रायल कोर्ट द्वारा उक्त बिंदु पर तैयार किया गया था, जिसने ऐसा प्रतीत होता है कि गलत तरीके से सरकार के पक्ष में फैसला किया गया है। वादी। यहां तक कि अतिरिक्त लिखित बयान में भी, बिक्री विलेख को रद्द करने की राहत को वाद–विवाद में जोड़ा जाता है निचली अदालत के समक्ष क्षेत्राधिकार को फिर से उठाया गया प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (अपीलकर्ता)। ऐसा होने पर, उपधारा (1–A) का वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं है आक्षेपित निर्णय और डिक्री को बचाएं। कारणों से, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कानून नंबर 1 का पर्याप्त प्रश्न अधिसूचना के तहत तदनुसार निर्णय लिया जाता है दिनांक 20.06.1963 (ऊपर उद्धृत), धारा 8 के तहत जारी उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1956, उत्तर प्रदेश राज्य में 1–1–2008 से निहित भूमि। 01.07.1963. और धारा 82 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उक्त

अधिनियम के साथ उत्तर प्रदेश जमींदारी की धारा 331 और भूमि सुधार अधिनियम, 1950, सिविल कोर्ट के समक्ष मुकदमा पार्टियों के बीच, कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

22. **<u>पर्याप्त प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दें:–</u>**

अपीलकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि महंत टहल दास का दिसंबर, 1957 में निधन हो गया। और वादी (प्रतिवादी) ने कोई कदम नहीं उठाया 1957 से मुकदमे में संपत्ति का कब्जा लेना अप्रैल, 1968। और इस बीच, बुद्ध दास, जो अंदर थे व्यवसाय, दिनांक 05.05.1962 के बिक्री विलेख को निष्पादित किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के पक्ष में, जैसा कि यह है दलील दी गई कि मुकदमा समय पर रोक दिया जाता है। इसके जवाब में, वादी/प्रतिवादी की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि बिक्री विलेख को रद्द करने की सीमा कहां से शुरू होती है? जब वादी को यह अधिकार देने वाले तथ्य उपकरण रद्द कर दिए गए, पहली बार उसे पता चला। जहां तक बिक्री विलेख को रद्द करने का संबंध है, मैं इससे सहमत हूं। वादी/प्रतिवादी के विद्वान वकील की दलील कि अनुच्छेद 59 अनुसूची के भाग–IV में निहित है परिसीमा अधिनियम, 1963 के लिए तीन वर्ष की सीमा का प्रावधान है ज्ञात होने की तारीख से दस्तावेज रद्द करना वादी के लिए। उक्त अनुच्छेद को इस रूप में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है नीचेः–

"भाग IV– डिक्री और उपकरणों से संबंधित मुकदमे

मुकदमे का विवरण	परिसीमन की अवधि	समय जिसमें से अवधि शुरू होती है
59. रद्द करना या एक अलग रख दें उपकरण या आदेश या आदेश के लिए एक का पुनरावलोकन ठेका।	तीन साल	जब तथ्य हकदार वादी को यह कहना चाहिए उपकरण या डिक्री रद्द या अलग रख दें या अनुबंध रद्द सबसे पहले जाना जाता है उसके लिए.

23. यह कहने की जरूरत नहीं है कि कृषि क्षेत्र से पहले उत्तर प्रदेश शहरी के तहत राज्य में निहित नगरपालिका सीमाए क्षेत्र जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम) 1956 की संख्या IX, उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम के प्रावधान, 1939, ऐसी कृषि भूमि पर लागू था। मेरे पास है पहले ही चर्चा की जा

चुकी है कि विचाराधीन भूमि किसमें निहित है? 1 जुलाई, 1963 से राज्य में वर्ष 1957 में जब टहल दास की मृत्यु हो गई, तो भूमि यूपी के तहत शासित थी। किरायेदारी अधिनियम, 1939 1 जुलाई, 1963 के बाद, उत्तर प्रदेश अधिनियम सं 1963 1956 का IX किस देश में भूमि के संबंध में प्रवर्तनीय था? प्रश्न। उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का नियम 98, यह प्रावधान है कि मुकदमों को न्यायालय के भीतर स्थापित किया जाना आवश्यक है उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों के परिशिष्ट में निर्दिष्ट अवधि जमींदारी और भूमि सुधार नियम, 19582। नियम 98 है नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:–

"98. *मुकदमा, आवेदन और अन्य कार्यवाही परिशिष्ट I में निर्दिष्ट–*

(i) की स्थापना निम्नलिखित में विनिदष्ट समय के भीतर की जाएगी। उनके लिए क्रमशः परिशिष्ट कहा गया, और

(ii) उनके संबंध में देय न्यायालय–शुल्क क्या होगा? जैसा कि उक्त के सातवें कॉलम में निर्दिष्ट किया गया है परिशिष्ट।

उपर्युक्त नियमों के परिशिष्ट की मद संख्या 31, मुकदमा दायर करने के लिए तीन साल की सीमा प्रदान की गई उन लोगों के लिए जो निहित होने की तारीख पर कब्जे में हैं और जिस मामले में जमीन का कब्जा है, उसमें छह साल गैरकानूनी तरीके से लिया गया या बनाए रखा गया, भूमिधर का एक हिस्सा है, सिरदार या असामी। टहल दास की मृत्यु के बाद से 1957, वर्ष 1968 में एक मुकदमा दायर किया गया था, इस अवधि के रूप में तीन साल के साथ–साथ छह साल पहले ही वादी की मृत्यु हो गई और वादी – दूज दास निश्चित रूप से बाहर रहे हरिद्वार में भूमि का कब्जा लिए बिना सात साल से अधिक समय तक सवाल, तारीख से जमीन विरासत में मिलने का आरोप है। वास्तव में मुकदमा था वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था यानी मृत्यु के ग्यारह साल बाद तहल दास।

24. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र जमींदारी की धारा 64 और धारा 82 उत्सादन और भूमि सुधार अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. IX) 1956 के अध्याय VIII में निहित प्रावधान और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम का अध्याय X, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 1951 का I, उत्तर प्रदेश अधिनियम IX में उधार लिया गया है 1956 में। इस प्रकार, निम्नलिखित के तहत मुकदमों वाले प्रावधान 1951 के उत्तर प्रदेश अधिनियम I की धारा 209 किसके लिए लागू होती है? उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1956 संख्या IX के तहत

कार्यवाही। यह है इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जब वादी ने पाया कि संस्था कब्जे के लिए राजस्व न्यायालय के समक्ष मुकदमा प्रतिबंधित है समय के साथ, उन्होंने सिविल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 का लाभ, जो कब्जे के लिए मुकदमे के लिए 12 साल की सीमा प्रदान करता है। इसलिए, जहां तक सिविल कोर्ट के समक्ष संस्था का सवाल है जहां तक इसका संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा किसके द्वारा प्रतिबंधित है? समय हालांकि सक्षम के समक्ष एक ही राहत अदालत को पहले से ही सीमा द्वारा रोक दिया गया था। पर्याप्त कानून संख्या 2 के प्रश्न का तदनुसार उत्तर दिया गया है।

25. **पर्याप्त प्रश्न संख्या 3 का उत्तरः–**

प्रतिवादी नंबर 1 और प्रतिवादियों के वकील 2/अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि भूमि और संपत्ति मुकदमा 1 जुलाई, 1963 से राज्य में निहित है (जैसा कि चर्चा की गई है) उपरोक्त मुकदमा आवश्यक पार्टियों के गैर–शामिल होने के लिए बुरा है यानी उत्तर प्रदेश राज्य और गांव सभा में इसके जवाब में, वादी/प्रतिवादी की ओर से, मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया संहिता के आदेश I के नियम 13 में निहित प्रावधान सिविल प्रक्रिया, 1908। और यह तर्क दिया जाता है कि पार्टियों के शामिल नहीं होने पर आपत्ति, स्टैंड माफ। मैं संहिता के आदेश I के नियम 13 को उद्धृत करना चाहूंगा सिविल प्रक्रिया, 1908, जो निम्नानुसार हैः–

13. ***गैर–जुड़ने वाले या गलत बयान के बारे में आपत्तियां–*** *सभी गैर–जुड़ने या गलत बयान के आधार पर आपत्तियां पार्टियों को जल्द से जल्द संभव अवसर पर लिया जाएगा और, उन सभी मामलों में जहां मुद्दों को हल किया जाता है, या उससे पहले इस तरह का समझौता, जब तक कि आपत्ति का आधार न हो बाद में उत्पन्न हुआ, और ऐसी कोई भी आपत्ति नहीं ली गई माना जाएगा कि इसे माफ कर दिया गया है।''*

इस तर्क के जवाब में, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील प्रतिवादी 1 और 2/अपीलकर्ताओं ने नियम की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया संहिता के उसी आदेश I के 9, जिसमें यह प्रावधान है कि ''कोई भी मुकदमा गलत या गैर–जोड़ के कारण नहीं हारा जाएगा। पक्षकारों की संख्या, और न्यायालय प्रत्येक वाद सौदे में कर सकता है जहां तक अधिकारों का संबंध है, मामला विवादों में है और वास्तव में इसके सामने पार्टियों का हित। बशर्ते कि इस नियम में कुछ भी शामिल न होने पर लागू नहीं होगा आवश्यक पार्टी में प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने के लिए, यह है यह देखना आवश्यक

है कि क्या आपत्ति गैर के बारे में है आवश्यक पक्ष का पक्षकार लिखित में उठाया गया है प्रतिवादी नंबर 1 और 2/अपीलकर्ताओं के बयान या नहीं? मुझे प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उठाई गई कोई याचिका नहीं मिली। और उनके लिखित बयानों में 2, जो कि बुरा होने के लिए उपयुक्त है राज्य या गांव सभा में शामिल न होना। सिद्धांत की दृष्टि से श्री राम बनाम जगन्नाथ ए.आई.आर. 1976 मामले में निर्धारित कानून एस.सी. पीजी 2335 और बिहारी लाल बनाम बिहारी लाल में निहित एक। भूरी देवी ए.आई.आर. 1997 एस.सी. पृष्ठ 1879 में 1183, यह न्यायालय यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादियों को करना चाहिए समिति में शामिल न होने पर आपत्ति जताई है पार्टियां जल्द से जल्द हों और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है इसे अब दूसरे अपीलीय चरण में उठाया जाए। में परिस्थितियों, मेरे पास असहमत होने का कोई कारण नहीं है याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील वादीध्प्रतिवादी कि प्रावधान को ध्यान में रखते हुए नियम 13 में निहित, गैर–शामिल होने वाले के बारे में आपत्ति राज्य या ग्राम सभा की राशि माफ कर दी गई है। तदनुसार प्रश्न संख्या 3 का उत्तरवादी/प्रतिवादी पक्ष में किया गया है?

26. **अन्य प्रस्तुतियाँः–**

वादी/प्रतिवादी की ओर से, किसका ध्यान दिया जाए? इस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के पैरा –11 में शामिल किया गया है ***संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी मामले में फेसला (2001) 3 एससीसी 179,*** और तर्क दिया कि अपील में है नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 का उल्लंघन, 1908 की अनुमति नहीं दी जा सकती। उक्त निर्णय का पैरा–11 क्या है? नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

'' यहां तक कि संहिता की पुरानी धारा 100 के तहत (1976 से पहले) संशोधन), तथ्य की एक शुद्ध खोज के लिए खुला नहीं था दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती। हालांकि विधि आयोग ने कई मामलों को नोटिस किया है। परस्पर विरोधी निर्णय। यह नोट किया गया कि निपटने में दूसरी अपील, अदालतें तैयार कर रही थीं और सफलतापूर्वक कई अवधारणाओं को अपनाना जैसे कि, एक मिश्रित प्रश्न तथ्य और कानून, तथ्यों से निकाला जाने वाला एक कानूनी निष्कर्ष साबित हुआ, और यहां तक कि यह मुद्दा भी कि मामला नहीं हुआ है नीचे दी गई अदालतों द्वारा ठीक से संपर्क किया गया। यह था जनता के मन में भ्रम पैदा करना धारा 100 के तहत दूसरी अपील का वैध दायरा और उच्च न्यायालयों पर अनावश्यक रूप से बोझ डाला था बड़ी संख्या में दूसरी अपील। धारा 100 थी, इसलिए, संशोधन करने का सुझाव दिया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि दूसरी अपील का अधिकार मामलों तक ही

सीमित होना चाहिए जहां कानून का एक सवाल शामिल है और ऐसा सवाल कानून एक महत्वपूर्ण कानून है। (वस्तुओं का विवरण देखें और कारण)। प्रवर समिति जिसमें संशोधन किया गया है बिल को संदर्भित किया गया था कि दूसरी अपील का दायरा मुकदमों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि मुकदमेबाजी न बढ़ सके एक लंबी अवधि के लिए। कारण, जाहिर है, की आवश्यकता नहीं है उपधारा के तहत कानून के किसी भी प्रश्न को तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए संहिता की धारा 100 की धारा (4)य हालांकि इस तरह कारणों को उप–धारा के परंतुक के तहत दर्ज किया जाना है (5) किसी अन्य पर सुनने की शक्ति का प्रयोग करते समय कानून का पर्याप्त प्रश्न, तैयार किए गए के अलावा उपधारा (4) के तहत।

27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून का कोई ठोस प्रश्न नहीं था इस अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया था और न ही माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तय कर सकता है जब इस अपील को स्वीकार किया गया तो कानून का पर्याप्त सवाल वर्ष 1977 में। लेकिन मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं धारा 100 में संशोधन 1–1–2011 से लागू हो गए हैं। 01.02.1977 और उसके तुरंत बाद दायर कई अपीलों में ये वास्तविक गलतियां शुरुआत में हुई थीं। लेकिन चूंकि इस न्यायालय ने पहले ही पर्याप्त प्रश्न तैयार कर लिया है इस न्यायालय में अपील प्राप्त होने के बाद कानून, गलती ठीक किया गया है और मेरी राय में, परिस्थितियों में, अपील को केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि कानून के पर्याप्त प्रश्नों का सुझाव नहीं दिया गया था अपील का ज्ञापन, खासकर जब गलती हो जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एक प्रामाणिक प्रतीत होता है। ***कोंडिबा दगाडू कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान गुजर (1999) 3 एससीसी 722,*** *में* यह देखा गया है कि धारा 100 का प्रावधान संविधान की शक्तियों को स्वीकार करता है। उच्च न्यायालय कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील पर सुनवाई करेगा? हालांकि इसके द्वारा इस उद्देश्य के साथ तैयार नहीं किया गया है यह सुनिश्चित करना कि वादी के साथ कोई अन्याय न हो, कहां प्रवेश के समय इस तरह के प्रश्न तैयार नहीं किए गए थे या तो गलती से या असावधानी से।

28. अंत में, वादी/प्रतिवादी की ओर से, यह है तर्क दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए कानून के प्रश्न 12.11.2002 को, पर्याप्त की परिभाषा को योग्य न बनाएं कानून का सवाल में इस संबंध में, इस न्यायालय का ध्यान शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार क्षितिज चंद्र पुरकैत बनाम संतोष कुमार पुरकैत (1997) 5

एससीसी 438 और हरि सिंह बनाम कन्हैया लाल (1997) 7 एससीसी 288। हालांकि, इस की राय में न्यायालय, वर्तमान में तैयार किए गए सभी तीन प्रश्न अपील केवल कानून के सवाल नहीं हैं, बल्कि पर्याप्त हैं। उपरोक्त दो मामले जिन पर निर्भरता है विद्वान वकील द्वारा पेश किया गया है वादी/प्रतिवादी, वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र की दलील उठाई गई थी ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के चरण से ही। अधिकार क्षेत्र के साथ–साथ सीमा का प्रश्न भी इस प्रकार है महत्वपूर्ण है कि यदि उठाई गई आपत्तियों से पहले भी, ट्रायल कोर्ट ने वाद–विवाद के आरोपों के आधार पर इसका पता लगाया कि मुकदमा समय से या कमी के कारण प्रतिबंधित है अधिकार क्षेत्र, यह आदेश VII नियम के तहत वाद को अस्वीकार कर सकता है। आदेश VII, नियम II, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्णय समाप्त करने से पहले, यह न्यायालय इसे महसूस करता है ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष का उल्लेख करना आवश्यक है तथ्य यह है कि बुद्ध दास एक काल्पनिक व्यक्ति थे, ऐसा प्रतीत होता है पूरी तरह से विकृत और रिकॉर्ड के खिलाफ। बुद्ध का नाम दास, चेला टहल दास, न केवल हस्तांतरणकर्ता के रूप में काम करते हैं दिनांक 05.05.1962 का पंजीकृत बिक्री विलेख लेकिन एक्सएच के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में भी। A–3 (1366 फसली के लिए) –कैलेंडर वर्ष 1958), पेपर नंबर 82–सी और एक पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 23.05.1961 (जो पेपर संख्या 61 है) ट्रेल कोर्ट रिकॉर्ड में सी)। विद्वान निचली अपीलीय अदालत मुकदमे द्वारा दिए गए इस तरह के निष्कर्षों की पुष्टि करने में कानून में भी गलती की है।

30. **निष्कर्षः–** चर्चा किए गए कारणों के लिए ऊपर और विशेष रूप से पर्याप्त पर दिए गए उत्तर कानून नंबर 1 का सवाल, यह अपील अनुमति के योग्य है चूंकि दीवानी अदालत के पास मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। तदनुसार, अपील को स्वीकार किया जाता है। विवादित फेसला और विद्वान अपीलीय अदालत एवं ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को रद्द किया जाता है। 1968 का मूल मुकदमा संख्या 85, पार्टियों के बीच को खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

(प्रफुल्ल सी पंत, जे.)

दि0: 23 फरवरी, 2006

स्वेता.